और... एक शेर

मेरी जिंदगी पे न मुस्करा, मुझे जिंदगी का अलम नहीं
जिसे तेरे गम से हो वास्ता, वो खिजां बहार से कम नहीं

-शकील बदायूंनी



लोकमत समाचार

तमसो मा ज्योतिर्गमय

इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता है, जितना कि वह बार-बार उन गलतियों को सोच कर होता है. ■ महात्मा गांधी

## संपादकीय

# डांस बार खोलने और बंद करने की चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दो सप्ताह में डांस बार खोलने के निर्देश दिए हैं. देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश सरकार के लिए अपने गिरेबान में झांकने जैसा है. आखिर, डांस बार बंद करने के मामले में कानूनी रूप से सरकार कहां कमजोर पड़ गई यह आज सबसे बड़ा सवाल है. डांस बार पर रोक लगाने की पूरी मंशा होने के बाद भी सरकार कोई ठोस कानूनी आधार पेश करने में क्यों पिछड़ गई? इससे तो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की विफलता ही साबित होती है. डांस बार पर पाबंदी का मामला औपचारिकता निभाने जैसा ही लगता है यह कहने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए. डांस बार पर रोक लगाने के लिए जारी अध्यादेश या आदेश को कोई कानूनी जामा नहीं पहनाया जाना सरकार के लिए मुसीबत बन गया. डांस बार के खिलाफ सरकार की ओर से कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर पाने के फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देना पड़ा. अगर डांस बार से अपराध बढ़ते हैं तो यह पूरी तरह कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है. ऐसे मामलों में किसी तरह की औपचारिकता निभाने की बजाय सरकार को ठोस कानूनी आधार के साथ पेश होना चाहिए था. यदि किसी चीज को सामाजिक कुरीति के रूप में देखा जाता है तो उसे खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जिसका कानूनी आधार भी हो. यह फैसला सरकार के लिए सबक है कि कोई निर्णय लेने से पहले उसकी कानूनी बारीकियों को अच्छी तरह समझ-बूझ ले, वरना इस तरह का हश्र होता रहेगा. 'संस्कृति और समाज' को संरक्षण देने वाली सरकार के सामने स्थायी रूप से डांस बार पर रोक लगाना एक बड़ी चुनौती है. डांस बार को किसका संरक्षण मिलता है यह सभी जानते हैं. फिलहाल यह सरकार के सामने एक चुनौती है और वह इसका सामना कैसे करती है यह भविष्य ही बताएगा. विरोधियों का कहना है कि यह बार मालिकों और सरकार के बीच मिलीभगत का नतीजा है. हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए कहा कि वह सैद्धांतिक रूप से डांस बार खोलने के खिलाफ हैं. अतः सभी कानूनी विकल्पों की तलाश जारी रहेगी. निश्चित रूप से कानूनी आधार के बिना इसे रोक पाना मुश्किल है. अश्लीलता के नाम पर सरकार को भले ही कोई आधार मिल जाए तो बात बन सकती है, अन्यथा काफी मुश्किल होगी. फिलहाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए दो सप्ताह में डांस बार खोलने पर निर्णय लेना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने 2005 से डांस बार पर लगी पाबंदी को पिछले माह हटा दिया था, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलने से बार मालिक अपना कारोबार शुरू नहीं कर सके थे. अतः उन्हें फिर से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ी. अबकी बार सरकार को जांच पड़ताल के बाद 60 बार मालिकों के आवेदन पर फैसला लेना है. जो भी हो, सरकार के लिए डांस बार पर पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं है जितना उसे पहले लग रहा था. सरकार को यह देखना होगा कि चूक कहां हुई. शीर्ष अदालत ने लाइसेंस जारी करने के आदेश के साथ सरकार से यह भी कहा है कि डांस बार से अश्लीलता न फैलने पाए इसका भी ध्यान रखा जाए. यानी सरकार लाइसेंस न दे तो भी अदालत की फटकार लगेगी और अश्लीलता रोक पाने में नाकामयाब रही तो भी फटकार लगेगी. इस तरह सरकार के सामने यह दोहरी चुनौती है. अश्लीलता ही तो सरकार के लिए परेशानी का सबब है. अब वह इससे कैसी निपटती है यह तो वही जाने लेकिन इस पर स्थायी रूप से रोक लगाने के लिए कानूनविदों से राय-मशविरा लेने की जरूरत है ताकि पाबंदी लगाने की स्थिति में फिर से औंधे मुंह गिरने की नौबत न आए. ■■

## चपरासी

लघुकथा



जगदीश कश्यप

यह संयोग ही था कि जिस विभाग में मेरा दोस्त काम करता था, उसीमें मेरा भी स्थानांतरण हो गया. एक बार उसने मेरी एक कहानी पर खुलकर समीक्षा की थी और पत्रों के माध्यम से हम गहरे मित्र बन गए थे. कथा-साहित्य पर उसका अद्भुत अधिकार था. स्थानांतरण पर मुझे खुशी हुई कि अब हम दोनों निकटवर्ती बनकर रह सकेंगे. मैंने उसे उत्साह-भरा पत्र लिखा कि मैं उसके यहां ब्रांच मैनेजर होकर आ रहा हूं. मैं वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि मेरे आने से पहले ही वह त्यागपत्र दे हमेशा के लिए अपने गांव जा चुका था.

उस दिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि विभाग की उस शाखा में वह चपरासी था. ■■

# कछुआ चाल से आगे बढ़ती योजनाएं



आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

अगला बजट आने में अधिक समय नहीं है. करीब तीन माह बाद मोदी सरकार का तीसरा बजट संसद में पेश हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, रेलमंत्री सुरेश प्रभु और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, बीजिंग, सिंगापुर सहित एक सौ देशों में भारत के 'क्रांतिकारी आर्थिक बदलाव' की ढपली बजा रहे हैं. अपनी ढपली, अपना राग बजाने को भला कौन रोक सकता है? लेकिन अमेरिकी, यूरोपीय, चीनी अथवा अति पिछड़े अफ्रीकी देशों के राजनयिक, उद्यमी, निवेशक, पत्रकार भारत में सत्ता व्यवस्था की 'कछुआ चाल' से दुविधा में फंस जाते हैं. यही कारण है कि पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान विदेशी पूंजी निवेश की अरबों डॉलर की घोषणाओं, समझौतों के क्रियान्वयन की कोई झलक नहीं दिख पा रही है. विदेशी दूर रहे, देशी निवेशक ही उलझन में हैं. वहीं योजना आयोग पर काली स्याही पोतकर केसरिया रंग से 'नीति आयोग' लिखकर टेबल-अलमारी-कुर्सियां बदल देने के बाद विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों को उनके बजट का एक तिहाई पैसा 8 महीनों से नहीं मिल पाने के कारण छोटे-छोटे काम तक रुक गए हैं. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के एक आर्थिक सलाहकार ने पिछले दिनों अनौपचारिक बातचीत में मुझे एक दिलचस्प जानकारी दी कि हाल तक उनके पास 'योजना आयोग' के लेटरहेड पर लिखे पत्र दिल्ली से आ रहे हैं. मतलब 'नीति आयोग' के अधिकारी अब तक पुराने लेबल से खानापूर्ति कर रहे हैं. निर्णय अधर में लटके हैं. असली निर्णय वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में हो रहे हैं. अंतिम स्वीकृति के अधिकार वहीं सुरक्षित हैं. अब प्रधानमंत्री कार्यालय के बिना पत्ता नहीं हिल सकता. इसलिए 'पतझड़' का इंतजार लंबा ही हो सकता है.

मोदी सरकार के नवगठित नीति आयोग के लिए स्वीकृत 600 में से 200 स्थान रिक्त पड़े हैं. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012 से 2017) का अब तक का लेखा-जोखा किए जाने का काम अटका हुआ है. तेरहवीं योजना बनाने के मुद्दे पर अनिश्चितता के काले बादल हैं. दुनिया के सामने देश के नेता 'बेसुरा' ढोल बजाकर दावा करते हैं कि 'हम चीन से मुकाबला करने वाले हैं. हमारी आर्थिक तरक्की चीन से बेहतर है.' जबकि असलियत यह है कि वर्तमान गति रहने पर हमारा सपना पूरा होने में 50 वर्ष लग सकते हैं. चीन या अमेरिका जैसे देशों में अगले 20 वर्षों की आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक संभावनाओं और खतरों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं, नीतियां बनती रहती हैं. सैकड़ों अधिकारी लगे रहते हैं. इसके अलावा गैरसरकारी स्तर पर अनेक 'थिंक टैंक' (शोध संस्थान) निरंतर दुनिया भर के देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते रहते हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाकेबंदी की जाती है. इसके विपरीत 'योजना' का अर्थ समाजवादी-साम्यवादी निकालकर केवल राजनीतिक सत्ता के हितों को ध्यान में रखकर 'तात्कालिक निर्णयों' को महान बताया जा रहा है. अरुणाचल प्रदेश को भारत का गौरवशाली हिस्सा कहते हुए हमें सचमुच खुशी होती है. लेकिन इस वित्तीय वर्ष के बजट में केंद्रीय योजनाओं के तहत अरुणाचल प्रदेश के लिए हुए 3200 करोड़ रुपए के प्रावधान में से अब तक केवल 800 करोड़ रुपए प्रदेश को दिए गए. इस तरह अरुणाचल की प्रगति होगी अथवा वहां आर्थिक कठिनाइयों से सामाजिक असंतोष बढ़ेगा? बिहार के बाद असम विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए संघ-भाजपा की कृपा से राज्यपाल बने आचार्यजी ने स्वयं घोषणा कर दी - 'मुसलमान पाकिस्तान या बांग्लादेश जा सकते हैं. हिंदुस्तान हिंदुओं का है. इसलिए बांग्लादेश से हिंदू भारत आकर बस सकते हैं.'

> 'नीति आयोग' के अधिकारी अब तक पुराने लेबल से खानापूर्ति कर रहे हैं. निर्णय अधर में लटके हैं. असली निर्णय वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में हो रहे हैं.




असम में बांग्लादेश से अवैध रूप से आने वाले लोगों की समस्या रही है. लेकिन हाल के वर्षों में सुरक्षा-तंत्र की सतर्कता से बहुत कम संख्या में घुसपैठ संभव है. पचास वर्षों के दौरान आए लोग सही मायने में एक नहीं तीन पीढ़ी के परिवार बन चुके हैं. असम में आदिवासी, मुस्लिम, ईसाई, सिख समुदाय के लोगों की अच्छी खासी संख्या है. वास्तव में उनकी संस्कृति मिली-जुली है. राजनीतिक अथवा आपराधिक तत्वों के कारण हिंसक घटनाएं होती हैं. उग्रवादी संगठन भी सक्रिय रहे हैं. ऐसी परिस्थिति में सांप्रदायिक मुद्दे से तनाव बढ़ाने का काम यदि केंद्र सरकार के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ही करने लगेंगे तो क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र शांत और खुशहाल रह सकेगा? जम्मू-कश्मीर में भाजपा की गठबंधन सरकार के रहते आए दिन पाकिस्तानी झंडों के साथ प्रदर्शनों का सिलसिला बढ़ना क्या खतरे की घंटी नहीं है. पंजाब में भाजपा-अकाली सरकार के राज्य में मादक पदार्थों (ड्रग्स) का भयावह असर बढ़ने से आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई है और पुराने घाव ताजा करने से असंतोष बढ़ रहा है. पंजाब विधानसभा के चुनाव भी सिर पर आ गए हैं. राजनीतिक-सांप्रदायिक तनाव बढ़ने से यह क्षेत्र फिर अतिसंवेदनशील हो जाएगा. इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक आचार संहिता पर विचार की आवश्यकता समझनी होगी. लोकतंत्र में सत्ताधारी दल और नेता बदलते रह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था और विकास में सामाजिक शांति और सहयोग जरूरी है. गैरभाजपा शासित प्रदेशों के नेताओं की शिकायतें एक हद तक पूर्वाग्रहप्रेरित कही जा सकती हैं, लेकिन भाजपाशासित राज्यों को भी तो केंद्र से आवंटित होने वाली धनराशि नहीं पहुंच पा रही है. वे सार्वजनिक रूप से बोल भी नहीं सकते. गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी में प्रदूषण का नुकसान तो सब को भुगतना होगा. इसलिए समय रहते सांप्रदायिक प्रदूषण रोकना जरूरी है, ताकि आर्थिक प्रगति का हिरण छलांग लगा सके. ■■

## कहानी आतंकवाद की

### हथियारों की कोई कमी नहीं

*इस्लामिक स्टेट के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और आतंकियों की बड़ी फौज किसी प्रशिक्षित सेना से कम नहीं है. खासकर गुरिल्ला वार में वे किसी भी सेना से कमजोर नहीं बैठते. ठीक-ठीक आंकड़े तो किसी के पास भी उपलब्ध नहीं हैं लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उसके पास करीब 2 लाख लड़ाके तो हैं ही जिनमें से 4 हजार विदेशी लड़ाके हैं. विदेशी यानी करीब 71 देशों के नागरिक. इनमें दो दर्जन भारतीय भी हैं. बगदादी की इस सेना को प्रशिक्षित किया है सद्दाम हुसैन की बाथ आर्मी के अधिकारियों ने. इनमें से दो अबु तुर्कमानी और अबु अंबारी एयर स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं. माना जाता है कि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की ट्रेनिंग कमांड संभालने वाले कम से कम 25 अधिकारी सद्दाम की सेना से बगदादी ने लिए हैं. बगदादी के आतंकी ठीक उसी स्वरूप में काम करते हैं जैसे किसी देश की सेना काम करती है. उनके कमांड बने हुए हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक यही कमांड संचालन करता है. हमला कैसे करना है, बचाव कैसे करना है, इसकी रणनीति बनाने वालों की टीम सीधे बगदादी के नेतृत्व में काम करती है. उसने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि उसका कोई कमांडर यदि जरा सा भी गड़बड़ करने की सोचे तो उसे तत्काल पता चल जाए. यही कारण है कि उसकी सेना में किसी भी देश की खुफिया एजेंसी पैठ नहीं बना पाई है.*

*बगदादी के पास विभिन्न क्षमताओं वाले करीब 150 टैंक, हजारों की संख्या में मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट लांचर, सैकड़ों आर्मर्ड स्काउट कार, हजारों की संख्या में आर्मर्ड व्हीकल और दूसरे हथियार हैं. ज्यादातर हथियार अमेरिका और रूस में बने हुए हैं. कुछ हथियार चीन, फ्रांस, पोलैंड, इटली, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, रोमानिया, आस्ट्रिया, जर्मनी और यूगोस्लाविया के भी हैं. इनमें से ज्यादातर हथियार इस्लामिक स्टेट ने हमला करके छीने हैं. जब अमेरिका ने इराक छोड़ा तो बहुत से हथियार भी इराक में ही छोड़ दिए. इराकी सेना इन हथियारों को संभाल नहीं पाई और बहुत से हथियार इस्लामिक स्टेट के हाथ लग गए. इराक के मोसूल पर कब्जे ने भी हथियारों का उसका खजाना भर दिया. सोवियत संघ में बने हथियार उसे सीरिया में मिले. सीरिया से ही उसने 3 फाइटर एयरक्राफ्ट भी छीना है. अब सवाल है कि गोला बारूद की सप्लाई कहां से हो रही है? नजर हथियारों के सौदागरों पर है.*

■ विकास मिश्र

# ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा यूरोप क्या करेगा?



मुकेश कुमार
जाने-माने पत्रकार

पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के बाद से यूरोप के हालात एकदम से बदल गए हैं. आतंक और आशंकाओं की छाया इतनी गहरा गई है कि जो यूरोप पहले शरणार्थियों के लिए बांह फैलाकर खड़ा हो गया था, अब वह उन्हें रोकने की जुगत में लग गया है. शरणार्थियों को स्वीकारने और उनको राहत देने के बजाय उन्हें आने से कैसे रोका जाए इस दिशा में प्रयास शुरू हो गए हैं. कई यूरोपीय देश अपनी सरहदों को बंद करने की कोशिश में जुट गए हैं तो कुछ ने परोक्ष रूप से जाहिर कर दिया है कि अब और शरणार्थियों का वे स्वागत नहीं करेंगे. निश्चय ही ये विचित्र स्थिति है और इससे सीरिया में चल रहे युद्ध की वजह से भाग रहे परेशान नागरिकों के लिए सुरक्षित शरणस्थली मिलने की संभावनाएं सीमित होती जा रही हैं.

> यूरोप ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है और उसके सामने बहुत ही गंभीर चुनौतियां हैं. उन्हें अपनी अवाम को शांत रखना है और शरणार्थियों की उपेक्षा से भी बचना है.

ये तो स्वाभाविक था कि पेरिस हमले के बाद यूरोपीय देश चौकन्ने हो जाते और इस बात की सावधानी बरतते कि शरणार्थियों की बाढ़ का लाभ उठाकर आतंकवादी भी उनके यहां घुसपैठ न करते. कोई भी देश अपने नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहेगा और फूंक-फूंक कर ही कदम आगे बढ़ाएगा. पिछले छह महीनों में दो बड़े आतंकवादी हमले झेल चुके फ्रांस के बारे में ये बात तो और भी सटीक बैठती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह अपनी मानवीय जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ लेगा.

दरअसल, यूरोपीय समाज बहुत डरा हुआ समाज है. तरक्की ने उसे बहुत डरपोक बना दिया है. वह दूसरों पर तो लगातार हमले करके अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करता रहता है, मगर जब कभी उस पर कोई छोटा-मोटा हमला भी हो जाता है तो वह ऐसे प्रतिक्रिया करता है मानो अब सब कुछ तबाह होने वाला है. वह तुरंत आक्रामकता दिखाने लगता है जैसे कि फ्रांस ने सीरिया पर हवाई हमले एकमुश्त बढ़ाकर किया. यही चरित्र अमेरिका का भी है. ट्रेड टॉवर पर हमले के बाद उसने सीधे अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी थी. इस तरह की प्रतिक्रियाओं के बहुत विपरीत परिणाम निकलते हैं, जैसा कि हम देख भी रहे हैं. अफगानिस्तान और इराक पर हमलों का नतीजा ही है जो आईएस के आतंकवाद के रूप में हमारे सामने है. सीरिया का संकट बढ़ता जा रहा है. तुर्की द्वारा रूसी विमान गिराने के बाद से तनाव और बढ़ गया है और युद्ध के फैलने की आशंकाओं में भी इजाफा हुआ है. एक छोटी सी चिंगारी या गलतफहमी हालात बिगाड़ सकती है. अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा शरणार्थियों की बाढ़ का नया दौर शुरू होना.

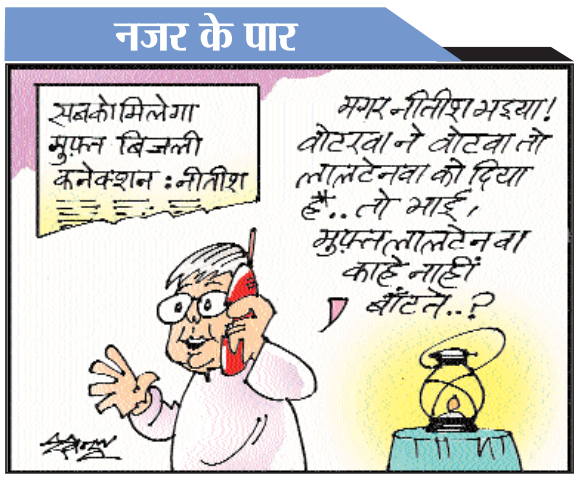

साफ है कि यूरोप ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है और उसके सामने बहुत ही गंभीर चुनौतियां हैं. उन्हें अपनी अवाम को शांत रखना है, सीरिया का युद्ध न फैले इसका ध्यान रखना है और शरणार्थियों की उपेक्षा से भी उसे बचना है. ये चुनौतियां यूरोपीय समुदाय के लिए अग्निपरीक्षा के समान हैं. अगर वह इसमें नाकाम हुआ तो यूरोप को विखंडन और विनाश से कोई नहीं बचा सकेगा. ■■

## नजर के पार




# एक नए मोदी का जन्म



वेद प्रताप वैदिक
वरिष्ठ पत्रकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो कई बातें एक साथ कहीं, उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनकी रेलगाड़ी अब पटरी पर आ रही है. पिछले डेढ़ साल से वह पटरी पर चढ़ी ही नहीं थी. वह चुनाव-अभियान की मुद्रा में ही खड़ी थी. खड़े-खड़े ही वह बस जोर-जोर से सीटियां बजा रही थी, कोरी भाप छोड़ रही थी और छुक-छुक कर रही थी. मोदी की रेलगाड़ी में सवार कई यात्री ऐसी-ऐसी आवाजें निकाल रहे थे कि प्लेटफार्म पर खड़ी जनता भौंचक हो रही थी. मोदी अभी तक प्रधानमंत्री-पद के उम्मीदवार की तरह सभाएं कर रहे थे. पहली बार लगा कि उन्होंने अब समझा कि वे भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं. एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री की तरह उन्होंने कहा कि सरकार का एक ही धर्म है- भारत प्रथम और उसका एक ही धर्मग्रंथ है- संविधान!

मोदी ने पहली बार नेहरू समेत सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को सराहा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बहुमत से चुनी गई है लेकिन वह चले



सर्वमत से! उन्होंने राजनीति को 'मेरे' और 'तेरे' में बांटने की बजाय 'हम' की भावना से चलाने की बात कही. अभी तो उनकी पार्टी ही सिर्फ 'मेरे' से चल रही है. उसमें से 'हम' की बात ही उड़ गई है. यदि वे देश को 'हम' के द्वारा चलाना चाहते हैं तो कहना पड़ेगा कि 'देर आयद, दुरुस्त आयद'! मोदी के गले में बंधा अहंकार और हीनता-ग्रंथि का पत्थर उन्हें दिनोंदिन डुबोए चला जा रहा था. अब आशा बंधी है कि वे तैर पाएंगे. सोनिया और मनमोहन सिंह को दिया गया बुलावा इस आशा को बलवती बनाता है.

यही नीति पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति भी चले तो पिछले डेढ़ साल में भारत का जो खेल बनते-बनते बिगड़ गया, वह भी सुधर जाएगा. संविधान के नाम पर फिजूल की नौटंकी रची गई, संसद और देश के दो दिन व्यर्थ हुए लेकिन उनमें से एक नए मोदी का जन्म हुआ, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है. इसका श्रेय आप बिहार को दें या झाबुआ-रतलाम की संसदीय सीट को दें या मोदी की अपनी चतुराई को दें-यह बहुत ही स्वागत योग्य घटना है. यदि मोदी की गाड़ी इस पटरी पर चलती रही तो वे निश्चित रूप से पांच साल पूरे करेंगे, अपनी प्रतिष्ठा कायम करेंगे, भाजपा मजबूत होगी और शायद वे देश के उत्तम प्रधानमंत्रियों में गिने जाएंगे. ■■

## तोल बोल

भारतीय संविधान में जितने संशोधन हुए हैं, दुनिया के अन्य किसी देश के संविधान में नहीं हुए हैं. अपनी सुविधा और लाभ के लिए संविधान संशोधन करना ठीक नहीं है.

■ मुलायम सिंह यादव, सपा प्रमुख

आमिर खान ने कब कहा कि वह देश छोड़ना चाहते हैं. मैं खुद उस कार्यक्रम में मौजूद था. यह आमिर के खिलाफ दुष्प्रचार है.



■ फारुक अब्दुल्लाह, पूर्व मुख्यमंत्री, जम्मू-कश्मीर

© लोकमत समाचार
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
0712-2423527 (7 lines) 6618555
Email : lsedit.ngp@lokmat.com
advt.ngp@lokmat.com circ.ngp@lokmat.com

## इतिहास पर नजर 29 नवंबर

आज ही के दिन 1963 में कनाडा का एक जेट विमान उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस भयावह दुर्घटना में विमान में मौजूद सभी 118 लोग मारे गए थे. ट्रांस-केनेडा एयरलाइंस के विमान ने मांट्रियल से टोरंटो के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ये विमान एक मैदान में जा गिरा. विमान का मलबा एक किलोमीटर की दूरी तक जा कर गिरा था. घायलों को बचाने के लिए एंबुलेंस बुलवाई गईं, लेकिन जब पता चला कि विमान में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं तो उन्हें वापस भेज दिया गया. घटनास्थल पर मौजूद जांचकर्ताओं ने शिकायत की कि कुछ लुटेरों ने विमान के मलबे और यात्रियों के सामान को लूट लिया था. इस दुर्घटना के कारण का कभी पता नहीं चल पाया और इसे कनाडा के इतिहास में सबसे भयावह विमान हादसों में गिना जाता है. ■■

- 1516-फ्रांस और स्विट्जरलैंड ने फ्रेईबर्ग के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया.
- 1830-पोलैंड में रूस के शासन के खिलाफ नवंबर विद्रोह शुरू हुआ.
- 1916-अमेरिका ने डोमिनिकन रिपब्लिक में मार्शल लॉ लगाया.
- 1944-अलबानिया को नाजी कब्जे से छुड़ाया गया.
- 1949-पूर्वी जर्मनी में यूरेनियम खदान में विस्फोट से 3700 मृत.
- 1970-हरियाणा सौ फीसदी ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पाने वाला पहला भारतीय राज्य बना.

## पाठकों के पत्र

### आतंकवाद और सुरक्षा

26/11 के मुंबई हमले के बाद अब फ्रांस में भी आतंकवादियों ने इसी तरह का हमला बोला. इसी तरह भारत में भी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं. कट्टरपंथी विचारधारा ही आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती है. वर्तमान समय में आतंकवाद की बाज जैसी नजर को देखते हुए देश की सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों को चौबीसों घंटे सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है. कट्टरपंथी विचारधारा से दूर रहकर ही देश का लोकतांत्रिक ढंग से विकास किया जा सकता है. सभी नागरिकों को यह बात समझनी चाहिए.

■ अब्दुल कय्यूम खान, नागपुर

### पाक की नीयत

पाकिस्तान की नीयत पूरा कश्मीर हड़पने की है. इसीलिए वह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है. लेकिन सच्चाई सारे संसार को मालूम है. पाक अधिकृत कश्मीर में जनता बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित है. अगर हमारा पड़ोसी अच्छा है तो हम शांति से रह सकते हैं, लेकिन यदि वह दुष्ट हो तो चौकस रहना ही श्रेष्ठ है.

■ विनोद नायडू, बल्लारशाह

## मालिक का दिमाग!

हास्य



एक लड़का टमाटर से भरी टोकरी साइकिल पर रख कर जा रहा था कि अचानक साइकिल पत्थर से टकरा गई और टोकरी गिर गई जिससे सभी टमाटर फूट गए.

भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी चिल्लाए : 'देख कर चलो भाई, कितनी गंदगी कर दी?'

भीड़ में से एक काका बोले, 'इतना चिल्लाने से अच्छा है यह सोचो कि इसका मालिक इसकी क्या हालत करेगा? पगार में से पैसे काट लेगा. इसकी कुछ मदद करो, लो मेरी तरफ से 10 रुपए.' कह कर उसने लड़के को दस रुपए दे दिए.

सभी ने सहानुभूति जताते हुए लड़के को 10-10 रुपए दिए.

लड़का खुश हो गया, क्योंकि मिली हुई रकम टमाटरों की कीमत से ज्यादा थी.

सभी के चले जाने के बाद एक व्यक्ति लड़के से बोला, 'बेटे, अगर काका नहीं होते तो मालिक को तू क्या जवाब देता?'

लड़के ने कहा, 'वो काका ही मेरा मालिक है.' ■■